

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 275 बेमेतरा, सोमवार 01 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

बीरभूम में बालू कारोबारी के घर मिला नोटों का पहाड़ व सोना

बीरभूम। जिले के मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र के राजधरपुर में एक रसूखदार बालू कारोबारी व एक तृणमूल नेता के करीबी लवन शेख के ठिकानों पर जिला पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी यानी नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तलाशी के दौरान घर व कार्यालयों के अलग-अलग हिस्सों और लॉकरों से 500 रुपये के नोटों के भारी-भरकम बंडल बरामद किए गए। बरामद रकम इतनी बड़ी है कि नोटों को गिनने के लिए बैंक अधिकारियों और मशीनों को मंगवाना पड़ा। पुलिस के दावों के अनुसार, मुख्य आरोपी का नाम लवण शेख है, जो लंबे समय से इलाके में बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस ने उसके घर से सठे दफ्तर की सघन तलाशी ली, तो वहां से कुल 49 लाख 75 हजार रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद हुई। इसके अलावा, तलाशी के दौरान 502 ग्राम (लगभग आधा किलो) सोने के गहने भी जब्त किए गए हैं। इस नकदी और सोने के स्रोतों को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से शमीम शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली में पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े दाऊद इब्राहिम के 9 गुर्गे गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध रखने वाले 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मुंबई के भगोड़े अंसवरुड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। इनको दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने इनके पास से हथियार और पाकिस्तान से भेजा गया विस्फोटक बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध दिल्ली, मुंबई, पंजाब समेत विदेश से हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है।

बरस्ती में नदी साफ करने वाले आकाश की तारीफ

मोदी ने गिनाई आमों की खूबियां बोले-आप आम नहीं, खास हैं

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड को संबोधित किया। यह कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और सरकार के आधिकारिक डिजिटल चैनलों पर प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में देशभर के आम उत्पादक किसानों की सराहना की है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम और समर्पण की बदौलत ‘फलों का राजा’ आम हर साल लाखों परिवारों तक पहुंचता है। पीएम मोदी ने बताया कि गर्मियों का मौसम आते ही देश में आम की चर्चा हर घर में शुरू होती है और शायद ही कोई ऐसा घर

होगा, जहां आम को लेकर उत्साह न हो। उन्होंने कहा, हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस (अल्मोसो), गुजरात का केसर, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी ने लंगड़ा आम की खासियत का भी जिक्र करते हुए कहा कि पकने के बाद भी इसका रंग कई बार हरा ही रहता है। उन्होंने बिहार के जर्दालू आम की सुगंध की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी खुशबू दूर से ही पहचान में आ जाती है। इसके अलावा उन्होंने चौसा और मालदा जैसी प्रसिद्ध किस्मों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि दक्षिण भारत में बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम और मलगोवा आम की



अपनी अलग पहचान है। वहीं, पश्चिम बंगाल का हिमसागर तथा ओडिशा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा आम भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा, जगह बदलती है तो आम का रूप, रंग और स्वाद भी बदल जाता है। यही भारत

की विविधता की खूबसूरती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारतीय आमों की पहचान केवल गांवों और स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे वैश्विक बाजारों तक भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने आम की खेती से जुड़े किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं

‘मन की बात’ के माध्यम से आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई-बहनों की प्रशंसा करता हूँ। पीएम ने कहा कि आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बल्कि बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छापे रहिए। प्रधानमंत्री के इस संदेश को आम उत्पादक किसानों के उत्साहवर्धन और भारतीय कृषि की विविधता को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान में लगभग 13 घंटे का समय लगा और डॉल्लिम को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक जीव को बचाने की कहानी नहीं बल्कि प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस सफल अभियान में भारत की पहली गंगा डॉल्लिम रेस्क्यू एम्बुलेंस ने बड़ी भूमिका निभाई।

भीषण गर्मी से बचाव और भारत के ‘देसी ड्रिंक्स’

देशभर में बढ़ते तापमान को देखते हुए पीएम मोदी ने नागरिकों से हीटवेव के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने लोगों को हाइड्रेटेड रहने, धूप में अनावश्यक बाहर न निकलने और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के पारंपरिक कुलिंग पेयों को प्राकृतिक औषधि बताते हुए ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना के तहत कई देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया: आम पन्ना, लस्सी, छाछ, सतू का शरबत, कोकम शरबत, सोल कढ़ी, पनाकम, नीर मोर, संभाराम और बेला पन्ना।

अब दुश्मनों की खैर नहीं

चीन और पाक मामलों के महारथी राजा सुब्रमणि बने नए सीडीएस....

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय रक्षा व्यवस्था के लिए 31 मई 2026 खास रहा। जनरल अनिल चौहान के रिटायर होने के बाद, जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कमान संभाल ली है। जब दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, तब भारत जैसे विशाल देश की तीनों सेनाओं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच एक मजबूत कड़ी का होना राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली शर्त है। जनरल सुब्रमणि का यह पदभार संभालना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक ऐसे समय में आए हैं जब भारतीय सेनाएं



अपने इतिहास के सबसे बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। जनरल राजा सुब्रमणि को भारतीय सेना का एक अत्यंत रणनीतिक और अनुभवी योद्धा माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान और चीन से जुड़े पेचीदा और संवेदनशील मामलों का गहरा जानकार माना

जाता है। उनके करियर ग्राफ पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण ‘नॉर्दन कमांड’ के साथ-साथ ‘सेंट्रल कमांड’ में भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं।सीडीएस बनने से पहले वे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर रह चुके थे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीएट में सैन्य सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। यह अनुभव उन्हें न केवल सीमाओं की भौगोलिक चुनौतियों को समझने में मदद करता है। बल्कि दिल्ली के गलियारों में बनने वाली रणनीतियों में भी उनकी पकड़ को मजबूत बनाता है। उनके पास पीवीएसएम और एवीएसएम जैसे विशिष्ट सेवा सम्मान हैं।

लिपुलेख मुद्दे पर नेपाल ने चला नया दांव

बालेन शाह ब्रिटेन को बनाना चाहते हैं मध्यस्थ

नई दिल्ली। नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को संसद में एक बड़ा बयान देते हुए भारत के साथ विवादित लिपुलेख मुद्दे पर ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग की है। बालेन शाह ने इस विवाद को द्विपक्षीय स्तर से ऊपर उठाकर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है, जिसे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक पैंतरे के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को संसद में एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद पर खुलकर अपनी



बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें यह अहसास हुआ कि मामला केवल एक पक्षीय नहीं है। शाह के मुताबिक, ‘सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है।

पोर्ट इलाके में बेकाबू मिनी बस ने बाइक को मारी भीषण टक्कर

कोलकाता। महानगर कोलकाता के पोर्ट अंचल के वेस्ट पोर्ट थाना अंतर्गत गार्डनरोच सर्कुलर रोड पर शनिवार दोपहर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। लाल बाजार पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मटियाबुर्ज-हावड़ा रूट की एक तेज रफ्तार मिनी बस ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बार-बार हो रहे इन हादसों के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पुलिस की यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

400 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की थमी सांसें, तीन गंभीर घायल

चमोली। जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. घटना में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया. बता दें कि घटना देवाल के ल्वाणी गांव में उस वक्त घटी, जब 6 लोग कार में सवार होकर देहरादून से देवाल के वाक गांव जा रहे थे. इसी दौरान कार अनियंत्रित हुई और सीधे 400 मीटर गहरी खाई में जा समाई. वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और गांव के लोग मौके पर पहुंची।

2 इंजीनियर सस्पेंड

साकेत बिल्डिंग हादसे में अब तक 5 की मौत फरार मालिक की तलाश कर रही पुलिस.....

नई दिल्ली। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत ढहने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पांच लोगों की मौत मामले में दो इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दक्षिण जोन के उपायुक्त की तरफ से जारी एक आदेश के माध्यम से सहायक इंजीनियर (भवन), सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर (भवन) को शनिवार को सईदुल अजायब इलाके में स्थित इमारत के निरीक्षण में हुई चूक के लिए



निलंबित किया गया है। इस हादसे के बाद कई एजेंसियों ने व्यापक बचाव अभियान चलाया। रविवार को मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई जबकि मलबे से कई लोगों को निकालकर अस्पताल में

एडमिट कराया गया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इमारत गिरने की घटना के बाद कुल 11 मरीजों को लाया गया था। इन 11 में से, तीन लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, तीन मरीज भर्ती हैं।

तीन को मृत अवस्था में ही लाया गया था, वहीं दो लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। हादसे के चश्मदीद ने घटना के बारे में बताया कि हमारी जानकारी के मुताबिक एक शख्स मिसिंग है, जिसे अभी ट्रैक किया जा रहा है। युवक ने बताया कि एक आंटी जो मेस चलाती थी उनकी डेथ हो गई है वो नेपाल की रहने वाली हैं। 15-16 छात्र वहां बैठकर खाना खा रहे थे और मेस की टीन पर इमारत का मलबा गिरा और अगर टीन की जगह कोई बिल्डिंग होती तो हादसा और बड़ा हो जाता। अस हादसे में 4-5 लोगों की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले को दी 739 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने कहा-जनता के बीच पहुंचकर सरकार दे रही अपने काम का रिपोर्ट कार्ड...

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार का दायित्व है कि वह जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का हिसाब दे, उनकी समस्याएं सुने और समाधान सुनिश्चित करे। इसी सोच के साथ राज्य सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से आमजन के बीच पहुंचकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज दुर्ग जिले के स्वर्गीय झाड़ूम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर को

संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले को दी 739 करोड़ 38 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर दुर्ग जिले को 739 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 251 लोककल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 362 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 376 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के 153 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परियोजनाएं दुर्ग जिले के विकास को नई

सुशासन का सरकार



दिशा देने के साथ नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्ग में सर्वसुविधायुक्त संयुक्त जिला कार्यालय

भवन के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि बेहतर प्रशासनिक अधोसंरचना से नागरिक सेवाओं में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा सुनिश्चित

होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक मई से प्रदेश में सुशासन तिहार का आयोजन निरंतर जारी है और 10 जून तक राज्य के सभी 33 जिलों में यह अभियान संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आयोजित समाधान शिविरों के माध्यम से न केवल समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, बल्कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि शासन अब कार्यालयों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता तक पहुंचकर सेवा देने की दिशा में कार्य कर रहा है।

सुवेंदु अधिकारी की नई टीम तैयार

35 दिग्गज नेता आज बनेंगे कैबिनेट मंत्री

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन का दूसरा चरण सोमवार को पूरा होने जा रहा है। सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 35 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना (राज्य सचिवालय) में आयोजित होगा, जहां राज्यापाल आएन रवि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ



दिलाएंगे। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई।



विकास का ढोंग या भ्रष्टाचार का खेल? गीदम नगर पंचायत में जनता की गाढ़ी कमाई पर ठेकेदारी राज का बुलडोजर..!

गीदम/मूक पत्रिका

लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारी और नगरीय निकाय जनता के टैक्स से जमा होने वाली राशि के ‘मालिक’ नहीं, बल्कि ‘ट्रस्टी’ (रक्षक) होते हैं। लेकिन दतेवाड़ा जिले के गीदम नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 (बस स्टैंड के पीछे, व्यावसायिक दुकानों के सामने) से जो मामला सामने आ रहा है, वह वित्तीय अनुशासन की ध्वजजांघ उड़ाने और सरकारी धन के खुलेआम दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ प्रशासनिक कसावट की शिथिलता इस कदर हावी है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए नियम-कायदे को ताक पर रखकर एक मजबूत और चालू कंत्रोटी नाली को जमींदोज करने का आत्मघाती टेंडर जारी कर दिया गया है। ?मामला सीधे तौर पर जनता की जेब पर ढका डालने और ‘विकास के नाम पर विनाश’ का खेल खेलने जैसा है। वार्ड क्रमांक 12 में बस स्टैंड के पीछे व्यावसायिक परिसर में पूर्व में होने वाले जलभराव और ड्रेनेज की गंभीर समस्या को दूर करने के नाम पर तत्कालीन समय में शासन ने लाखों रुपये स्वीकृत किए थे। जिस पर लगभग 7 6 लाख की भारी-भरकम राशि खर्च करके

न्यायालय में 2 जून को हाजिर होने भवानी शो रूम सराईपाली को सूचना पत्र जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर न्यायालय सारंगढ़ ने भवानी शो रूम सराईपाली तहसील सराईपाली जिला महासमुंद को 2 जून 2026 को आवकारी प्रकरण 202510321300007 में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया है। सुनवाई तिथि में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की दशा में शो रूम के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। पश्कार छ.ग.शासन बनाम शिवकुमार सारथी वगैरह, साकिन- डुमुरसिंधा में थाना सरिया के अपराध क्र. 205/ 2025 धारा 34(2), 59 (क) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मोटर सायकल बजाज सीटी 100 क्रमांक छत्र 06 तरह 6388 में अवैध रूप से शराब का परिवहन किए जाने पर वाहन को जप्त किया गया है। इस वाहन के पंजीकृत स्वामी मनोज थुरिया के द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 2023 में वाहन का विक्रय भवानी शो रूम सराईपाली में किया है।

अनुरेखक (सिविल) और प्रयोगशाला परिचारक के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर ने बायोलॉजी से बारहवीं उत्तीर्ण युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए 08 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इसी प्रकार ड्राइंग के साथ बारहवीं उत्तीर्ण या बारहवीं उत्तीर्ण युवाओं से जल संसाधन विभाग के अनुरेखक (सिविल) पद के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन लिया जाएगा। शासन के निर्देश पर राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने पर परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिसमें आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पद्म पुरस्कार हेतु जनजातीय समुदाय के योग्य व्यक्तियों से नामांकन 5 जून तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़,। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने योग्य सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जनजातीय समुदायों के व्यक्तियों से कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कोसीर रोड कॉलेज के पास सारंगढ़ में 5 जून 2026 तक आमंत्रित किया है। भारत सरकार के पद्म पुरस्कार हेतु जनजातीय समुदायों से योग्य एवं प्रेरणादायक व्यक्तियों की पहचान एवं नामांकन आमंत्रित किये जा रहे हैं जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, लोक संस्कृति पारम्परिक ज्ञान, चिकित्सा, खेल अथवा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। जनजातीय गरिमा सम्मान 2026 हेतु नायकों की पहचान एवं नामांकन प्रपत्र अनुसार, आवेदक जाति व्यवसाय पद या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आवेदक किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट या असाधारण सेवा प्रदान की हो। आवेदक उत्कृष्टता के साथ-साथ लोक सेवा का प्रदर्शन करना चाहिए। आवेदक कला, समाज कार्य, सार्वजनिक मामले, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, खेल या अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। आवेदक सेवारत सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिको को छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद, बेमेतरा में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा, बैलागाड़ी में निकली बारात, 21 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। सामाजिक परंपराओं, वैदिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक उल्लस के बीच आयोजित इस समारोह में जिले के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शुभ मुहूर्त में वर-वधुओं ने वैदिक संरोच्चार के बीच सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा जिले को एक महत्वपूर्ण सौगात देते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी की, जिससे जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के लिए वरदान-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के

बेमेतरा

विकास का ढोंग या भ्रष्टाचार का खेल? गीदम नगर पंचायत में जनता की गाढ़ी कमाई पर ठेकेदारी राज का बुलडोजर..!



चाहिए था। लेकिन यहाँ ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ की तर्ज पर पूरी नाली मजबूत हिस्सा भी शामिल है नया बनाने का एकमुश्त टेंडर निकाल दिया गया, जो सीधे तौर पर वित्तीय कदाचार की श्रेणी में आता है।?छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के नियमों और वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी चालू और मजबूत सरकारी संपत्ति को समय से पहले बिना किसी ठेस तकनीकी कारण के नष्ट करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि ऐसा किया जाता है, तो स्थानीय निधि संपरीक्षा में इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज होना तय है। इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कमलनाथ बनाम भारत संघ’ व अन्य कई मामलों में ‘पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन’ (सर्वजनिक न्यास का सिद्धांत) को स्थापित करते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया है कि सरकारी धन का दुरुपयोग होने पर अदालतें चुप नहीं बैठेंगी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के

कोमटपल्ली व्यपवर्तन योजना के लिए चार गांवों में भूमि अधिग्रहण पर जनसुनवाई 3 से 6 जून तक

बीजापुर/मूक पत्रिका

कोमटपल्ली (कोकमपल्ली) व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण के लिए भोपालपटनम तहसील के चार गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन के तहत 3 से 6 जून तक पामगल, कोतापल्ली, उस्कालेड और कोंगुपल्ली में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।जारी अधिसूचना के अनुसार चारों गांवों में कुल 9.282 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिससे 113 परिवार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। परियोजना की लागत 774.57 लाख रुपए आंकी गई है। योजना पूरी होने पर कोतापल्ली, उस्कालेड, कोंगुपल्ली और पामगल क्षेत्र की करीब 300 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा

42 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी जीवन लाल यादव सेवानिवृत्त



सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले के कुटेला निवासी श्री जीवन लाल यादव, जो पशुपालन विभाग में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, 31 मई 2026 को अपनी लंबी एवं गौरवशाली सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक एवं सम्मान समारोहों का आयोजन किया गया। श्री यादव की प्रथम नियुक्ति 20 जून 1984 को बोंदा में हुई थी। इसके बाद उन्होंने विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए पशुपालकों एवं ग्रामीणों के बीच एक कर्मंद, सरल एवं जनहितैषी अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी सेवा के अंतिम चरण में वे भेड़वून में पदस्थ थे, जहां से उन्होंने 31 मई 2026 को सेवानिवृत्ति ग्रहण की सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री यादव द्वारा सामाजिक सेवा का संदेश देते हुए प्रंजल स्कूल में बच्चों को फ्ल एवं कोल्टिड्सक का

घरघोड़ा/मूक पत्रिका

तहसील घरघोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छेडोरिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार केंद्र परिसर में लगे हैंडपंप से निकलने वाला जल अत्यधिक आयरनयुक्त, दुर्गंधयुक्त एवं संधिध गुणवत्ता का है, जिसे मजबूरी में छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पीना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी जैसे संवेदनशील केंद्रों का उद्देश्य बच्चों एवं महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना होता है, लेकिन यहां की स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की दुर्गंध इतनी तेज है कि उसका सामान्य उपयोग भी कठिन हो गया है। लगातार ऐसे दूषित जल के सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव और बीमारियों का खतरा बढ़ने की

‘मन की बात’ कार्यक्रम का 134वां संस्करण

आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर एवं जिला भूमि अर्जन अधिकारी ने किसानों, ग्रामीणों और अन्य हितधारकों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है।बॉक्स

एक नजर में

- कुल भूमि अधिग्रहण : 9.282 हेक्टेयर
- प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार : 113
- परियोजना लागत : 774.57 लाख रुपए
- सामाजिक प्रभाव प्रतिपूर्ति प्रावधान : 5 लाख रुपए
- सिंचाई लाभ : करीब 300 हेक्टेयर कृषि भूमि

जनसुनवाई कार्यक्रम

- 3 जून : पामगल (41 परिवार)
- 4 जून : कोतापल्ली (30 परिवार)
- 5 जून : उस्कालेड (39 परिवार)
- 6 जून : कोंगुपल्ली (3 परिवार)

समय : सुबह 11 बजे

मिलेगी।पामगल में 3 जून को 4.319 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर 41 प्रभावित परिवारों के लिए, कोतापल्ली में 4 जून को 2.317 हेक्टेयर भूमि पर 30 परिवारों के लिए, उस्कालेड में 5 जून को 2.477 हेक्टेयर भूमि पर 39 परिवारों के लिए तथा कोंगुपल्ली में 6 जून को 0.169 हेक्टेयर भूमि पर 3 परिवारों के लिए जनसुनवाई होगी। सभी जनसुनवाई सुबह 11 बजे संबंधित ग्रामों में

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न

मकानों और पारिवारों का जानकारी डिजिटल माध्यम से हुई सुरक्षित

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विगत शनिवार को सफ़लतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह राष्ट्रीय अभियान 01 मई 2026 से शुरू होकर पूरे 30 दिनों तक चला। यह जिले की भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया गया है। जिले में इस कार्य को कुशलता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए 13 जनगणना का चार्ज (6 तहसील एवं 7 नगरीय निकाय) बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद, बेमेतरा में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा, बैलागाड़ी में निकली बारात, 21 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

समरसता का आदर्श-मुख्यमंत्री ने बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में स्वयं विवाह कर समाज के सुपने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहल युवाओं को सादगीपूर्ण विवाह, सामाजिक समरसता और अनावश्यक खर्चों में कमी लाने का सकारात्मक संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उदाहरण समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और सामाजिक समानता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बारािश को बताया शुभ संकेत-मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य के दौरान वर्षा होना इंद्रदेव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन भी प्रकृति के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है, जो नवदंपतियों के सुखद और समृद्ध भविष्य का शुभ संकेत है।

बैलागाड़ी में निकली बारात बनी आकर्षण का केंद्र-समारोह का एक प्रमुख आकर्षण पारंपरिक बैलागाड़ी में निकली गई बारात रही। जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। पारंपरिक वाद्ययंत्रों, लोक-सांस्कृतिक माहौल और जनसहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। इस आयोजन ने ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक परंपराओं की

समरसता का आदर्श-मुख्यमंत्री ने बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में स्वयं विवाह कर समाज के सुपने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहल युवाओं को सादगीपूर्ण विवाह, सामाजिक समरसता और अनावश्यक खर्चों में कमी लाने का सकारात्मक संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उदाहरण समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और सामाजिक समानता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बारािश को बताया शुभ संकेत-मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य के दौरान वर्षा होना इंद्रदेव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन भी प्रकृति के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है, जो नवदंपतियों के सुखद और समृद्ध भविष्य का शुभ संकेत है।



‘मन की बात’ कार्यक्रम का 134वां संस्करण

आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर एवं जिला भूमि अर्जन अधिकारी ने किसानों, ग्रामीणों और अन्य हितधारकों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है।बॉक्स

एक नजर में

- कुल भूमि अधिग्रहण : 9.282 हेक्टेयर
- प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार : 113
- परियोजना लागत : 774.57 लाख रुपए
- सामाजिक प्रभाव प्रतिपूर्ति प्रावधान : 5 लाख रुपए
- सिंचाई लाभ : करीब 300 हेक्टेयर कृषि भूमि

जनसुनवाई कार्यक्रम

- 3 जून : पामगल (41 परिवार)
- 4 जून : कोतापल्ली (30 परिवार)
- 5 जून : उस्कालेड (39 परिवार)
- 6 जून : कोंगुपल्ली (3 परिवार)

समय : सुबह 11 बजे

मिलेगी।पामगल में 3 जून को 4.319 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर 41 प्रभावित परिवारों के लिए, कोतापल्ली में 4 जून को 2.317 हेक्टेयर भूमि पर 30 परिवारों के लिए, उस्कालेड में 5 जून को 2.477 हेक्टेयर भूमि पर 39 परिवारों के लिए तथा कोंगुपल्ली में 6 जून को 0.169 हेक्टेयर भूमि पर 3 परिवारों के लिए जनसुनवाई होगी। सभी जनसुनवाई सुबह 11 बजे संबंधित ग्रामों में

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न

मकानों और पारिवारों का जानकारी डिजिटल माध्यम से हुई सुरक्षित

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विगत शनिवार को सफ़लतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह राष्ट्रीय अभियान 01 मई 2026 से शुरू होकर पूरे 30 दिनों तक चला। यह जिले की भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया गया है। जिले में इस कार्य को कुशलता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए 13 जनगणना का चार्ज (6 तहसील एवं 7 नगरीय निकाय) बनाए गए हैं।



आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल में केवल आयरन ही नहीं, बल्कि अन्य हानिकारक तत्वों की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी पुष्टि केवल वैज्ञानिक जांच के बाद ही संभव है। हालांकि अब तक न तो जल की गुणवत्ता की जांच कराई गई है और न ही किसी वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था की पहल की गई है। पेयजल गुणवत्ता की निगरानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) एवं जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी है, जबकि आंगनबाड़ी संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन है।

‘मन की बात’ कार्यक्रम का 134वां संस्करण



बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम दरामुड़ा (खरसिया विधानसभा) में उत्साहपूर्वक सुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का 134वां संस्करण आज 31 मई को खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दरामुड़ा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 134वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया गया।इस अवसर पर स्थानीय

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न



कुल 1227 गणना खंडों के अंतर्गत, 1394 प्राणकों और पर्यवेक्षकों की टीम ने घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से संकलित की है। यह सभी जानकारी जनकारी अब पूरी तरह से भारत सरकार के सर्वर पर सुरक्षित है। जिला प्रशासन ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में जिले के नागरिकों से प्राप्त सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990

के प्रावधानों के तहत, नागरिकों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

जनगणना 2027 का द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त किया है कि आगामी चरण में भी जिले के निवासियों का इसी प्रकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों से अनावश्यक सामाजिक व्यय में कमी आती है तथा समाज में समानता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने सभी नवदंपतियों से अपने वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास, सहयोग, संस्कार और आपसी सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की रही गरिमामयी उपस्थिति-इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, मंत्री श्री दयाल दास बघेल, मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, सांसद श्री विजय बघेल, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, पंडेरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, धरसीवा विधायक श्री अनुज शर्मा, राजिम विधायक श्री रोहित साहू, अभनपुर विधायक श्री इन्द्र कुमार साहू, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, नवदंपतियों के परिजन एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।यह संस्करण प्रेस विज्ञप्ति, समाचार पत्र प्रकाशन तथा जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक रिलीज के अनुरूप विस्तृत एवं सुव्यवस्थित रूप में तैयार किया गया है।

संपादकीय

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना इस बात की कानूनी घोषणा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है। इससे उन लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिली है।लोकतंत्र में किसी भी चुनाव की शुचित्ता इस बात पर निर्भर करती है कि जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया कितनी संवैधानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी है। यह तभी सुनिश्चित हो पाता है, जब मतदाता चुनाव में मतदान की वास्तविक पात्रता रखते हों और तमाम चुनावी कार्य स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराए

जाएं।इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है और वह समय-समय पर मतदाता सूची में संशोधन करता रहता है, ताकि जो व्यक्ति मतदान के लिए पात्र नहीं है या जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कुछराज्यों में पिछले दिनों इसे लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए।यहां तक कि इसके औचित्य पर भी सवाल उठाए गए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में

कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआइआर कराने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक दायित्व में जान फूंकती है। स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव की अनिवार्यता को आगे बढ़ाने में यह महत्त्वपूर्ण कदम है।गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सबसे पहले सवाल उठे थे। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के समय को लेकर प्रश्न उठाया था। उनका कहना था कि चुनाव से ठीक पहले ही यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, जबकि

निर्वाचन आयोग इसे एक साल पूर्व भी करवा सकता था। इसके बाद आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करने को लेकर भी विवाद हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और अंततः निर्वाचन आयोग को इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने पड़े।इसके बाद सवालों का यह सिलसिला उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचा और शीर्ष अदालत को फिर इसमें दखल देना पड़ा। बिहार में एसआइआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गईं थीं, जिनका निपटारा करते हुए न्यायालय

ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना इस बात की कानूनी घोषणा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है। इससे उन लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिली है, जिनके नाम तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि

कहीं आगे चलकर उनकी नागरिकता खतरे में न पड़ जाए। यह बात सच है कि चुनावों की शुचित्ता को बरकरार रखने के लिए मतदाता सूची में संशोधन जरूरी है, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से मताधिकार से वंचित न हो, इसकी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही है।पिछले दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से लाखों लोग मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदान नहीं कर पाए, वह वास्तव में चिंताजनक है।

शब्द बहुत हैं, मगर भावनाएं कम पड़ गई हैं, संवेदनाओं के शहर में अकेला होता मनुष्य

(शोभा जैन)

संतोष और प्रतिरोध समाज में स्वतः-साथ चलने वाला अयाचित भाव है। ऐसे में भावनाओं का आहत होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भावनात्मक अनुपस्थिति हमेशा शारीरिक अनुपस्थिति नहीं होती, लेकिन वह शारीरिक से कहीं अधिक गहरी और निपुण होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, जब हम बिना किसी रिश्ते, परिचय या पहचान के भी कुछ दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं।

वे दृश्य भले ही सड़क पर निकलती किसी की शव यात्रा का हो, किसी बच्चे का गुब्बारा न खीद पाने का रुदन या चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे नंगे पैर घूमते मासूम बच्चे, जो किसी चमचमाती कार का कांच अचानक साफ करने लगते हैं। भावुक व्यक्ति कभी सुविधा से चयन करने वाला नहीं होता, वह सूखी नदी या बंजर खेत देखकर भी उतना ही दुखी हो सकता है, जितना गमी के दिनों में दो-दिन घर में पानी न आने पर। भावनात्मक होना एक शुद्ध व्यक्ति की पहचान है, इसलिए भावना के हर शब्द नवजात होते हैं। नवजात का हृदय निश्छल पवित्र होता है।

बात छेटी-बड़ी नहीं होती है, भावनाएं छेटी-बड़ी होती हैं

हमारे सामूहिक मानस में स्वीकार्य यथार्थ होना तो भावनात्मक स्तर का होना चाहिए, लेकिन इसके उलट अब स्वीकार्य यथार्थ से भावनाओं का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता। कहने का आशय यह कि बात छेटी या बड़ी नहीं होती। छेटी या बड़ी होती है भावना। शब्द सामने आ जाते हैं, भावना पीछे रह जाती है। इसीलिए दुनिया में शब्दों की लड़ाई चलती है। याद रखना होगा कि भावना का हर तत्त्व नवजात है। वह कभी पुनरावृत्ति में जन्म नहीं लेती। भाव एक अचेतन तोत्रता का अनुभव है। हालांकि भावना और प्रभाव का प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन प्रभाव को भावनाओं और संवेगों से भ्रमित न करना महत्वपूर्ण है।

आज लोगों की भावना सुविधा के मुताबिक हो गई है। वे सड़क पर घुमाते अपने कुत्ते के लिए तो संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक भी, लेकिन दूसरों के बच्चों या सड़क के अन्य जीव के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया भावनात्मक स्तर पर सतही नजर आती है। हम बात भावनाओं की कर रहे हैं, लेकिन अब जो शब्द खबरों और बातचीत में गूँजते हैं- बलात्कार, हत्या, जन्महंसार, आत्महत्या, भीड़-हत्या, देहेज हत्या, बाल शोषण, मानव तस्करी, आतंकवाद, अग्रहण आदि, वे हमारी भावनाओं को कितना आहत करते हैं? घटनाओं का अतिरिक्त हमारी

विचार–पक्ष

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और लोकतंत्र की असली परीक्षा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि वह मानव सभ्यता के भविष्य का निर्णायक मोड़ बनती जा रही है। जिस गति से यह तकनीक विकसित हुई है, उसने दुनिया को आश्चर्यचकित भी किया है और चिंतित भी। अभी तक विज्ञान और तकनीक मनुष्य के हाथों में उपकरण थे, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहली ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और सृजन करने की क्षमता के साथ स्वयं को निरंतर विकसित कर रही है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मगुरु, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता इसके खतरों को लेकर गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं।

क्या एआई मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी?

(तलित गर्ग)

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि वह मानव सभ्यता के भविष्य का निर्णायक मोड़ बनती जा रही है। जिस गति से यह तकनीक विकसित हुई है, उसने दुनिया को आश्चर्यचकित भी किया है और चिंतित भी। अभी तक विज्ञान और तकनीक मनुष्य के हाथों में उपकरण थे, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहली ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और सृजन करने की क्षमता के साथ स्वयं को निरंतर विकसित कर रही है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मगुरु, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता इसके खतरों को लेकर गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं। हाल ही में वर्तमान पोप लियो चौदहवें द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में व्यक्त की गई चिंताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध को नैतिक नहीं बनाया जा सकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। दुनिया को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

पोप ने सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में एआई को मानवता के समक्ष उभरती सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी परिवर्तन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली शक्ति बनती जा रही है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना होना चाहिए। उनका संदेश मानव-केंद्रित विकास की अवधारणा को बल देता है, जिसमें विज्ञान और तकनीक को नैतिकता, मानवीय गरिमा और करुणा के अधीन रखा जाए। पोप की यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मानवीय आह्वान है कि एआई की अंधी दौड़ में मानवता, संवेदना और नैतिकता का क्षरण न होने दिया जाए। आज जब महाशक्तियां एआई के माध्यम से प्रभाव और नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा में लगी हैं, तब पोप का यह संदेश विश्व समुदाय को संयम, उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है।

पोप ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एल्गोरिथ्म युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता और तकनीक को मानव विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता। पोप ने चर्च के सामाजिक सरोकारों से जुड़े अपने इस आधिकारिक पत्र में पहली बार एआई को प्रमुख विषय बनाया, जो इस बात का संकेत है कि इसका प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव जीवन, समाज और वैश्विक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से एआई आधारित स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस तकनीक को पूर्णतः मानवीय नियंत्रण में नहीं रखा गया तो यह युद्ध, शोषण और दासता के नए रूपों को जन्म दे सकती है। पोप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र



करने का आह्वान करते हुए उसका आशय तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अमानवीय उपयोग पर रोक लगाना बताया। उनका कहना था कि युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय अंततः नैतिकता, करुणा और विवेक पर आधारित होने चाहिए, उन्हें मशीनों के हवाले नहीं किया जा सकता। आज जब अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हैं और युद्ध तकनीकों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, तब पोप का यह संदेश मानवता के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में सामने आया है कि तकनीक मनुष्य की सेवक बने, स्वामी नहीं; और विकास का केंद्र मानव गरिमा, संवेदना तथा विश्वशांति ही रहे।

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है।

आज वही संकट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लाखों लोगों के कार्यों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। ग्राहक सेवा, लेखन, अनुवाद, लेखांकन, सूचना प्रबंधन, प्रोग्रामिंग और कार्यालयी कार्यों में मनुष्य की आवश्यकता तेजी से घट रही है। मशीनों कम लागत, अधिक गति और निरंतर कार्य क्षमता के कारण मनुष्य का स्थान ले रही हैं। इससे केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक असंतुलन और आर्थिक विषमता भी गहराएगी। जिन देशों और कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण होगा, आर्थिक शक्ति भी उन्हीं के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। इससे विश्व व्यवस्था में असमानता का नया



स्वरूप उभरेगा।

इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न वैश्विक सुरक्षा का है। आज अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हुई हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व का नया संघर्ष बन चुकी है। जैसे कभी परमाणु हथियारों और घातक अस्त्र-शस्त्रों के माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ था, वैसे ही अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की सामरिक शक्ति बन रही है। स्वायत्त हथियार प्रणाली, बुद्धिमान ड्रोन और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने वाली युद्ध तकनीकें मानवता के लिए भयावह संकेत हैं। यदि युद्ध का निर्णय मशीनों के हाथों में चला गया तो संवेदना, विवेक और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मशीनों के लिए मानव जीवन केवल आकड़े होंगे। ऐसी स्थिति महाविनाश की संभावना को जन्म दे सकती है। पोप की यह चेतावनी इसी संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है कि युद्ध का अंतिम निर्णय मानव विवेक के अधीन रहना चाहिए।

साइबर सुरक्षा भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण

नई चुनौतियों से घिर गई है। बैंकिंग व्यवस्था, विद्युत तंत्र, रक्षा नेटवर्क और संचार प्रणाली आज डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हैं। एआई आधारित साइबर हमले किसी भी राष्ट्र को कुछ घंटों में अस्थिर कर सकते हैं। झूठे संदेश, भ्रामक वीडियो, कृत्रिम चित्र और आवाजों के माध्यम से सामाजिक तनाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। सत्य और असत्य का अंतर मिटने लगा है। यह सूचना तंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए गंभीर संकट है। एआई का एक और नितानजनक पक्ष है-मानवीय नियंत्रण का कमजोर पड़ना। वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग मानता है कि भविष्य में ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित हो सकती है जो मनुष्य की क्षमता से कई गुना आगे निकल जाए। यदि ऐसा हुआ तो नियंत्रण का प्रश्न सबसे बड़ा संकट बनेगा। यह केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न होगा।

भारत के लिए यह विषय और अधिक महत्वपूर्ण है। भारत युवा शक्ति, विशाल जनसंख्या और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि एआई को बिना स्पष्ट नीति और नियंत्रण के बढ़ने दिया गया तो रोजगार, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भारत को विकास और नियंत्रण दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। एआई को रोकना समाधान नहीं है, लेकिन इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन रखना अनिवार्य है। भारत को ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक विकास के लिए हो, लेकिन रोजगार संरक्षण, डेटा सुरक्षा, नैतिक मानदंड और युद्ध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी एआई के उपयोग हेतु साझा नियम और अंतरराष्ट्रीय संधियां आवश्यक हैं।

आज सबसे बड़ा प्रश्न तकनीक का नहीं, मानवता का है। क्या मनुष्य अपनी बनाई हुई शक्ति पर नियंत्रण बनाए रख सकेगा? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन को समृद्ध बनाएगी या उसे नियंत्रित करेगी? क्या विकास संवेदनाओं से बड़ा हो जाएगा? क्या एआई रूपी विस्फोट मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी? यही वे प्रश्न हैं जिन पर दुनिया को गंभीर चिंतन करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा यदि मानवता केन्द्रित रही तो यह सभ्यता को नई ऊंचाइयों दे सकती है, लेकिन यदि यह शक्ति नियंत्रण और नैतिकता से मुक्त हो गई तो यह मानव इतिहास के सबसे बड़े संकट एवं महाविनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज आवश्यकता तकनीकी प्रगति की नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण प्रगति की है-जहां मशीनें विकसित हों, किंतु मानवता सर्वोच्च बनी रहे। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

देश व समाज हित में डीजल व पेट्रोल की बचत के साथ-साथ स्थाई सादगी समय की मांग!

(दीपक कुमार त्यागी)

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते जिस समय पूरे विश्व के सामने ऊर्जा संकट व मंहगाई सुरसा राक्षसी की तरह मूंह खोलकर के देश की दौलत को निगलने के लिए खड़ी है, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीजल व पेट्रोल को बचाने व सोना ना खरीदने की सभी देशवासियों से अपील की है, क्योंकि मोदी की इस अपील पर अमल करने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला बोझ कम से कम कुछ तो कम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी के द्वारा चलाई जा रही इस राष्ट्रहित की मुहिम में शामिल होने की होड़ लग गई है। हालांकि अभी तो अधिकतर लोग सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस मुहिम में ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन सांकेतिक ही सही एक बहुत अच्छी पहल में कम से कम लोगों के जुड़ने की शुरुआत तो हुई और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस पहल पर बड़े पैमाने पर आम लोग भी अमल करेंगे।

वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे-धीरे

रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया। जिसके बाद से ही देश भर में ज्यूडिशियरी, शीर्ष नौकरशाह, कर्मचारी व आम जनमानस तक भी मोदी की इस मुहिम में अहं रहे हैं। शासन-प्रशासन के शीर्ष स्तर पर काबिज बैठे हुए ताकतवर लोगों में देश भर में वाहनों के लंबे-चौड़े काफिले का त्याग करने की फिलहाल तो एक होड़ लगी हुई है। हालांकि उन लोगों का यह कदम वास्तव में दिल से खर्चों में कटौती करते हुए जीवन में सादगी अपनाने की धरातल पर एक स्थाई पहल है या सिर्फ मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी कुछ पोस्ट डालकर के वाहवाही लूटने की एक नौटंकी मात्र है, यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम युद्ध के माहौल के चलते जब पूरी दुनिया ऊर्जा व आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील पर भारत में धरातल पर अमल शुरू होना देश व समाज हित के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।

लेकिन विचारणीय तथ्य यह भी है कि क्या

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह मुहिम कुछ समय की ना होकर के देश व समाज हित में धरातल पर दीर्घकालीन स्थाई रूप ले पायेगी, हालांकि यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्धों के चलते बेहद ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है,

उस माहौल का स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब वह दौर आ गया है जब देश व समाज के हित में जनता के टैक्स के पैसे के दम पर राजा-महाराजाओं की तरह पूरी शानो-शौकत व ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे शासन-प्रशासन के लोग सादगी से जीवनयापन करने की आम जनमानस के सामने नज़ीर पेश करते हुए लोगों को भी सादा जीवन उच्च विचार के लिए प्रेरित करें। वैसे भी देखा जाए तो अब देश व दुनिया में वह दौर शुरू हो गया है, जब देश व समाज के हित की बातें सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बैठकर के आम जनमानस पर अपने विचार या नियम-कानून बना कर के थोप देने मात्र से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उस पर अमल करवाने के लिए शासन-प्रशासन में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी स्वयं अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सादगी व जवाबदेही को अपनाकर उदाहरण पेश करना चाहिए, तब ही आम जनमानस भी उन लोगों की देखा-देखी उस पर अमल करने का कार्य करेगा। लेकिन आज के वीवीआईपी बनकर के दिखाने वाले दौर में जिस तरह के राजसी ठाट-बाट के साथ कुछ राजनेताओं व शासन-प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग सरकारी व निजी दौरों के दौरान अनाप-शनाप खर्चा करते हैं, क्या ऐसे लोग के द्वारा देश व समाज हित में उन सभी अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही कटौती करने की पहल करके जनता के सामने एक बड़ी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए।

विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरकारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह

चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी मंशंगी गाड़ियों के लंबे-चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपना भौकाल बनाने के लिए व दिखावे के लिए ली गयी अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को भी अब बिचकूल सीमित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चंद लोग सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों की कृपा से सरकारी अमल के की आड़ में जनता के टैक्स के पैसों पर मौज मस्ती करते हुए जनता का ही आये दिन उत्पीड़न करते हैं, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके हमारे प्यारे देश में धनपशु, दलाल व अपराधी तक की सरकारी सुरक्षा व सुविधाओं के भौकाल का आनंद लें रहे हैं, जो नियम कायदे व कानून पर्यंत देशभक्त देशवासियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। देश व समाज हित में जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दी गई धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्योग-धंधों आदि के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास पर खर्च हो। देश की जनता के टैक्स का धन देश के विकास और आम जनमानस की भलाई में लगे, न कि वीवीआईपी बनने की चाहत के बेफिजूल के खर्चों और शानो-शौकत में

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में महंगाई दर

3.8 प्रतिशत

वॉशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिका में महंगाई (मुद्रास्फीति) दर अप्रैल में बढ़कर 3.8 फीसदी पहुंच गई। यह पिछले तीन वर्षों का सबसे उच्च



स्तर है। यह वृद्धि ईंधन और खाने-पीने की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल के कारण हुई है। यह संकेत है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव अमेरिकी लोगों की भी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि अप्रैल में महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 3.8 फीसदी हो गई, जो मार्च में 3.5 प्रतिशत थी। यह मई 2023 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। मासिक आधार पर कीमतों में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, हालांकि मार्च में यह बढ़ोतरी 0.7 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गैस के अलावा कई अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं। इससे संकेत मिलता है कि महंगाई लंबे समय तक बनी रह सकती है और इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महंगाई अभी भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 2 फीसदी तय लक्ष्य से काफी ऊपर है। इसका अर्थ है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती करने से बच सकता है। कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगला कदम ब्याज दरों में कटौती की बजाय बढ़ोतरी भी हो सकता है। अनाज और ऊर्जा जैसी अस्थिर श्रेणियों को हटाने पर मुख्य महंगाई दर अप्रैल में 3.3 फीसदी रही, जो पिछले महीने 3.2 प्रतिशत थी। यह नवंबर 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि एक सकारात्मक संकेत यह रहा कि मुख्य कीमतों में मासिक वृद्धि केवल 0.2 फीसदी रही। उच्च कीमतों का असर लोगों की आय पर भी पड़ा है। अप्रैल में लोगों की आय मार्च की तुलना में स्थिर रही, लेकिन महंगाई को समायोजित करने के बाद वास्तविक आय में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

रूस ने आर्मेनिया को दीधमकी: कछा-ईयू से बढ़ाई नजदीकियां, तोड़लेना होगा निलंबन

मॉस्को, एंजेंसी। रूस के नेतृत्व वाले आर्थिक संगठन ने आर्मेनिया को बड़ी चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि वह आर्मेनिया को बाहर निकाल सकता है। दरअसल, आर्मेनिया अब यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होना चाहता है। रूस के गुट को आर्मेनिया की यह बात पसंद नहीं आ रही है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस बैठक में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने कहा कि आर्मेनिया के इस कदम से हमारी आर्थिक सुरक्षा को भारी खतरा है। इन चारों देशों के नेताओं ने अपने अधिकारियों को एक आदेश दिया है। अधिकारी दिसेंबर में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में देखा जाएगा कि आर्मेनिया को हटाने से क्या असर पड़ेगा। इन नेताओं ने आर्मेनिया से अपने देश में जनमत संग्रह कराने को भी कहा है। वे चाहते हैं कि आर्मेनिया की जनता खुद चुने कि उन्हें यूरोपीय संघ में जाना है या रूस के आर्थिक गुट में रहना है। हालांकि, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान इस मांग को पहले ही ठुकरा चुके हैं। यह सारा विवाद आर्मेनिया के संसदीय चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ है। आर्मेनिया में सात जून को वोट डाले जाएंगे। निकोल पाशिन्यान साल 2018 से प्रधानमंत्री हैं। वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले साल अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना झगड़ा खत्म कराया था। इसके बाद से आर्मेनिया लगातार अमेरिका और यूरोपीय संघ के करीब जा रहा है। पाशिन्यान सरकार ने रूस के सैन्य संपादन (सीएसटीओ) में भी शामिल होना बंद कर दिया है। आर्मेनिया का पश्चिम की तरफ झुकाव रूस को नाराज कर रहा है।

रुबियो-इशाक डार की मुलाकात, शांति के लिए अमेरिका ने पाक के सामने रखी अब्राहम समझौते की शर्त

वाशिंगटन/ इस्लामाबाद, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने में पाकिस्तान एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की है। स्टेट डिपार्टमेंट की इमारत में बंद कमरों के भीतर दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने वाले देशों से एक बड़ी मांग की है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ शांति वार्ता में जुटे देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। इसके साथ ही वे इस्त्राइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करें। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। रुबियो ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की ओर से निभाई जा रही भूमिका के लिए इशाक डार को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि दोनों देश सुरक्षा को बेहतर करने और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सार्थक साझेदारी को मजबूत करने पर

सहमत हुए हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बताया कि बैठक में सुरक्षा को



लेकर भी बात हुई। रुबियो ने पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से किए गए हालिया आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बीते 24 मई को बलूचिस्तान प्रांत में एक शटल ट्रेन में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 24 लोग मारे गए थे

देश-विदेश

बातचीत और बमबारी साथ-साथ: दशकों

बाद इस्त्राइल-लेबनान की सीधी सैन्य वार्ता

यरुशलम, एजेंसी। इस्त्राइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बीच शुक्रवार को इस्त्राइली सैनिक दक्षिणी लेबनान के दिब्बीन गांव में दाखिल हो गए। इससे उनका अभियान देश के भीतर और आगे बढ़ गया। इसी दौरान इस्त्राइली हवाई हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पांच लोगों की मौत देहर कानौन अल नहर और अब्बासियेह गांवों पर हुए हवाई हमले में हुई, जबकि एब्बा गांव में एक नगरपालिका पुलिसकर्मों की जान चली गई। उधर, वॉशिंगटन स्थित पेंटागन में लेबनान और इस्त्राइल के सैन्य अधिकारियों के बीच दशकों बाद पहली प्रत्यक्ष सैन्य वार्ता हुई। छह सदस्यीय लेबनानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने इस्त्राइली अधिकारियों से मुलाकात की। पेंटागन ने वार्ता को सकारात्मक बताया और कहा कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा व



अगले सप्ताह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा राजनीतिक नेताओं के साथ होने वाली बातचीत का आधार बनेंगे। लेबनानी प्रतिनिधिमंडल ने संघर्षविराम को व्यापक रूप से लागू करने और 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम की निगरानी करने वाली समिति को फिर से सक्रिय करने की मांग रखी। लेबनानी

अधिकारियों ने यह भी कहा कि संघर्षविराम के पूर्ण क्रियाव्ययन के बाद सीमा पर लेबनानी सेना की तेनाती और दक्षिणी लेबनान से इस्त्राइली सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत में कहा कि किसी भी अन्य मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले संघर्षविराम का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बीच इस्त्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के लिए निकासी चेतावनी जारी की, जिसके बाद सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ा। दक्षिणी लेबनान में योहमोर और जवतर अल-शकिंयेह गांवों के आसपास इस्त्राइली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच झड़पें जारी रहीं। हिजबुल्लाह ने दावा किया

कि उसके लड़ाकों ने योहमोर के भीतर इस्त्राइली सैनिकों को निशाना बनाया। ये गांव ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले के पास स्थित हैं, जो इजरायल-लेबनान सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी मोर्चे का दौरा करते हुए कहा कि उनकी सेना लितानी नदी पार कर रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है और हिजबुल्लाह को करारा झटका दे रही है। उन्होंने कहा कि इस्त्राइल बेरूत, बेका घाटी और पूरे मोर्चे पर अभियान चला रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच गुरुवार को युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने को लेकर एक प्रारंभिक सहमति बनने की खबर सामने आई।

ईरान से डील को लेकर दुविधा में ट्रंप: परमाणु और होर्मुज संकट पर टली बड़ी घोषणा, अंतिम फैसले का अब भी इंतजार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को क्वाइट हाउस में एक बड़ी बैठक की। यह बैठक सिचुएशन रूम में हुई। इसमें ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ चर्चा की। इस बैठक में ईरान के साथ चल रहे तनाव पर बात हुई। दो घंटे की इस बातचीत के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। दोनों देशों के बीच युद्धविराम बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने पर भी चर्चा हो रही है। ईरान ने कहा है कि यह सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। इस बैठक से पहले ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अंतिम फैसला लेना चाहते हैं। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने समाचार एजेंसी एपी को नाम न छपाने की शर्त पर बताया कि ट्रंप अपनी शर्तों पर ही समझौता करेंगे। वह ईरान के परमाणु मंसूबों को रोकना चाहते हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि ईरान को यह मानना होगा कि वह कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान के पास अभी 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। यह 60 प्रतिशत तक शुद्ध है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90 प्रतिशत शुद्धता चाहिए होती है। ट्रंप चाहते हैं कि इस सामग्री को जमीन से खोदकर निकाला जाए। फिर इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। नए समझौते में होर्मुज जलमार्ग को खोलना सबसे बड़ी शर्त है। यह दुनिया



प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने ओमान को भी इस मामले में दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालीबाफ ने अमेरिका पर भरोसा करने से इनकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइलों से रियायतें हासिल करते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि उनका ध्यान अभी सिर्फ युद्ध खत्म करने पर है। वे परमाणु योजना पर बात नहीं कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्ला और इस्त्राइल के बीच भी लड़ाई रुके। इसके साथ ही ईरान अपनी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम भी वापस चाहता है।

सीएचआईपीएस और सेल्सफोर्स के बीच सहयोग; छत्तीसगढ़ के ‘डिजिटल द्वार’ को मिलेगी मजबूती, डिजिटल गवर्नेंस में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (सीएचआईपीएस), जो राज्य में ई-गवर्नेंस की नोडल एजेंसी है, ने आज सेल्सफोर्स के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत म्यूल्सॉफ्ट को ‘डिजिटल द्वार’ के तकनीकी आधार के रूप में लागू किया जाएगा। ‘डिजिटल द्वार’ राज्य का एकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। यह पहल सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ विज़न के अनुरूप छत्तीसगढ़ में एक जुड़ा हुआ और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, राज्य ने महसूस किया कि बिखरी हुई प्रणालियाँ और डेटा के समन्वय की मैनुअल प्रक्रिया प्रभावी और त्वरित शासन में बाधा बन रही थीं। इसी चुनौती से निपटने के लिए सीएचआईपीएस ने म्यूल्सॉफ्ट आधारित एपीआई-चालित इंटीग्रेशन रणनीति अपनाई। इसके तहत ‘डिजिटल द्वार’ को एक केंद्रीकृत एपीआई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ राज्य के सभी विभाग एक सुरक्षित और नियंत्रित प्रणाली के माध्यम से डेटा सेवाओं को साझा और उपयोग कर सकेंगे। इससे पहले जिन प्रक्रियाओं में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे, अब वही डेटा तुरंत एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। नागरकीकृत इंटीग्रेशन प्रेमवर्क बड़े स्तर पर एकरूपता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जबकि सीएचआईपीएस सभी डेटा प्रवाह पर केंद्रीकृत निगरानी और नियंत्रण बनाए रखेगा। इससे विभागों के बीच तेज़ और अधिक प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन में सेल्सफोर्स की कंसल्टिंग पार्टनर कंपनी वाटसू ने अहम भूमिका निभाई। इस सहयोग के सकारात्मक परिणाम राज्य की शासन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। विभिन्न विभागों में मैनुअल डेटा आदान-प्रदान की प्रक्रियाओं और इंटीग्रेशन में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं, रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होने से निर्णय लेने और सेवाओं की डिलीवरी की गति भी तेज हुई है। केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था ने डेटा सुरक्षा और अनुपालन को भी मजबूत बनाया है।

शांगरी-ला डायलॉग: तकनीक से मजबूत होगा हिंद-प्रशांत क्षेत्र

सिंगापुर, एजेंसी। भारत ने शांगरी-ला संवाद 2026 के दौरान उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयासों और अकादमिक सहभागिता के जरिये एक स्थिर व सुरक्षित हिंद-प्रशांत बनाने की बात कही है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक्स पर कहा, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना की मजबूती, रक्षा औद्योगिक सहयोग तथा उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारियों पर अग्रणी थिंक टैंक व शिक्षाविदों से भारतीय रक्षा कूटनीति पर प्रकाश डाला।

रक्षा सचिव ने एक स्थिर, सुरक्षित और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए भारत की रक्षा कूटनीति विषय पर क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहभागिता के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। पोस्ट के अनुसार, इस चर्चा में सिंगापुर में भारतीय उच्चयुक्त शिल्पक अबुले भी उपस्थित थीं, जो इस चर्चा के राजनयिक महत्व को रेखांकित करती है। बातचीत का मुख्य जोर सैन्य-से-सैन्य सहयोग मजबूत करने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर रहा। इस बीच, अमेरिकी रक्षा (युद्ध) मंत्री पीट हेगसेथ ने मुख्य भाषण से पहले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक हितों की रक्षा के दृढ़दर्शी दृष्टिकोण की रूपरेखा स्पष्ट की। उनकी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की यह चौथी यात्रा है।

रणनीतिक जुड़ाव की जरूरत पर जोर भारत-अमेरिका ने शांगरी-ला संवाद में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा-सुरक्षा सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष, नाटो एडमिरल ज्यूसेपे डेगो डैगन के साथ भी बातचीत की। इस दौरान, रक्षा सचिव राजेश सिंह ने अमेरिका के इंडोपैकॉम (हिंद-

भारत ने डाला प्रौद्योगिकी साझेदारी पर प्रकाश

प्रशांत कमान) के कमांडर, एडमिरल सैमुअल जे. पपरो के साथ चर्चा की। उन्होंने नाटो के साथ निरंतर रणनीतिक जुड़ाव बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। रक्षा सचिव ने नाटो एडमिरल ज्यूसेपे केवो डैगन के साथ वैश्विक-क्षेत्रीय सुरक्षा



चुनौतियों में हो रहे बदलावों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा, राजेश सिंह की वार्ता का केंद्र रणनीतिक संवाद बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों में हो रहे बदलावों पर विचारों का आदान-प्रदान करना था। उन्होंने प्रमुख बहुपक्षीय रक्षा संगठनों के साथ रचनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी बताया। दोनों पक्षों ने उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी पर प्रमुख थिंक टैंक और शिक्षाविदों से भी चर्चा की।

राजनयिक संबंध गहरे करेंगे: ऑस्ट्रेलिया: संवाद के दौरान ऑस्ट्रेलिया के उप

प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉर्लेस ने कहा, हम सहयोग को मजबूत करने के लिए राजनयिक और रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में है। यह शांगरी-ला संवाद एशिया का प्रमुख

रक्षा-सुरक्षा शिखर सम्मेलन माना जाता है, जहां एशिया-प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के रक्षा मंत्रियों, सैन्य प्रमुखों, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए जुटते

हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के संवाद में मुख्य भाषण देने की भी उम्मीद है। वह हिंद-प्रशांत में चीन से अमेरिकी रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए वाशिंगटन का पक्ष रखेंगे। हालांकि उन्होंने सिंगापुर पहुंचने पर पत्रकारों से शुरुआत में ही अपना रुख और एजेंडा प्रस्तुत किया। वह क्षेत्र में भारत को सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने में भारत काफी सक्षम है। संभव है कि वह भू-राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए ईरान से जारी युद्ध पर भी विचार रखें।

चीनकी सीक्रेट एजेंट निकलीं पूर्व अमेरिकीमेयर: अदालत में कबूला गुनाह, 10 साल के लिए जाएंगी जेल!

लॉस एंजेलिस, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक चौकाने वाली खबर आई है। अर्काडिया शहर की पूर्व मेयर एलीन वांग ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिकी सरकार



मंगेतर याओ‘निंग ‘माइक्र’ सन ने चीनी अधिकारियों के लिए काम किया। दोनों मिलकर ‘यूएस न्यूज सेंटर’ नाम की वेबसाइट चलाते थे। इस वेबसाइट के जरिए वे चीन का प्रचार करते थे। जून 2021 में एक चीनी अधिकारी ने वांग को एक लिंक भेजा था। यह लॉस एंजेलिस टाइम्स में छपा एक पत्र था। इसमें शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को झूठा बताया गया था। वांग ने कुछ ही मिनटों में इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया था। एलीन वांग नवंबर 2022 में अर्काडिया की सिटी काउंसिल में चुनी गई थीं। इसके बाद वे मेयर बनीं। जब उनके खिलाफ एफबीआई की जांच शुरू हुई, तो लोगों ने इस्तीफे की मांग की। लेकिन कांयवाहक मेयर पॉल चेंग ने कहा कि उनके हाथ कानून से बंधे थे। शहर के नियमों के मुताबिक किसी को दोषी साबित होने से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता था। एलीन वांग ने इस महीने की शुरुआत में खुद ही इस्तीफा दे दिया था।

कोई देश नहीं थोप सकता अपना वर्चस्व: अमेरिका की चीनको दो टूक, पीट हेगसेथ ने भारत को बताया ताकतवर देश

सिंगापुर, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शनिवार को कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और अपनी सेना को आधुनिकीकरण कर रहा

है। उन्होंने कहा कि भारत के पास भारी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षमता है, जो उसे उच्च-स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। हेगसेथ ने सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद के दौरान प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत खास



तौर से हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए हुए है। शांगरी-ला संवाद में बोलते हुए उन्होंने जिक्र किया कि भारत उच्च-स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए भारी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षमता का निर्माण भी कर रहा है। हेगसेथ ने कहा, ‘हमने क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने की भी प्रतिबद्धता जताई है।’ उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण के विस्तार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा-संबंधी संबंधों का भी आकलन किया। हेगसेथ ने क्षेत्र में अमेरिका की रक्षा रणनीति पर कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एशिया-प्रशांत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र की सुरक्षा असंतुलित रूप से अमेरिकी सैन्य शक्ति पर टिकी हुई है। उन्होंने देशों से अपनी रक्षा में गंभीरता से निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के संबंध कई वर्षों में सबसे बेहतर हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन सहित कोई भी देश अपना वर्चस्व थोप नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश और सहयोगियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकता है। हेगसेथ ने वैश्विक तनाव, पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों के बीच वॉशिंगटन का रुख बताया। इसके साथ ही इंडो-पैसिफिक में अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं पर बढ़ती अनिश्चितता को भी रेखांकित किया।

